

4

पत्र सं०-वि०व०संग्रह/संग्रह अमीन प्रत्यावेदन/2023-24/

45 /राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 19 अप्रैल, 2023

संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक),

.....सम्भाग,.....

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न अधोलिखित 15 सेवानिवृत्त संग्रह अमीनों श्री राजा राम, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री गिरीश चन्द्र सोनकर, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ श्रीमती कंचन श्रीवास्तव पत्नी स्व० उमाकान्त श्रीवास्तव, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री सुरेन्द्र कुमार, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ श्री परशुराम वर्मा, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री अशोक कुमार रावत, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री सुनीत कुमार गुप्ता, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री विष्णुदयाल सिंह, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री अनिल कुमार भट्ट, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री राम कुमार, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री अशोक कुमार दुबे, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, लखनऊ, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, अमेठी व श्री विभूतिनारायण मिश्र, से०नि० संग्रह पर्यवेक्षक, वाणिज्य कर, कानपुर।

द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक-06.11.2019 के दृष्टिगत पूर्व में स्वीकृत वेतनमान रू० 1200-2040 के स्थान पर रू० 1400-2300 का उच्चकृत वेतनमान रू० 2200-4000, 8000-13500 के वेतनमान का निर्धारण करते हुए बकाये के भुगतान के आदेश निर्गत किये जायें।

प्रत्यावेदन एकाधिक जोन से संबंधित हैं। अतः इनके निस्तारण में एकरूपता बनाये रखे जाने के उद्देश्य से न्याय निर्णय दिनांक-06.11.2019 के विरुद्ध विशेष अपील सं०-756/2020 के अस्वीकृत आदेश दिनांक-02.12.2020 के विरुद्ध योजित पुर्नविचार याचिका सं०-243/2021 का निस्तारण मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक-16.03.2023 द्वारा किया गया है। वर्तमान न्यायिक निर्णय दिनांक-16.03.2023 के आलोक में प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना है। यद्यपि पूर्व में ही पत्र सं०-1054 दिनांक-31.03.2023 द्वारा इस आशय के निर्देश निर्गत किये गये है कि प्राप्त प्रत्यावेदनो के निस्तारण किन मानदण्डो के आधार पर किये जायेगे, तथापि उपर्युक्त प्रत्यावेदन कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उ०प्र० के कार्यालय में भी प्राप्त हो गये है, जिनका निस्तारण संबंधित नियोक्ता संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) स्तर से किया जाना है। अतः एक बार पुनः मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मारकण्डेय सिंह व अन्य 11 के संबंध में पारित आदेश दिनांक-16.03.2023 में प्रतिपादित सिद्धान्तो का उल्लेख इस आशय से किया जा रहा है कि प्रत्यावेदन का निस्तारण अविलम्ब इन्हीं मानदण्डों के आधार पर किया जाये।

उपर्युक्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु मानदण्ड निम्न प्रकार है:-

(01)-राजस्व विभाग के पत्र सं०-15 दिनांक-24.01.2020 के बिन्दु सं०-14 के उपबिन्दु सं०-(i) से (vi) में उल्लिखित तथ्यों का समावेश इस कारण आवश्यक है कि इस पत्र द्वारा निर्गत व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 के पूर्व तक नहीं प्रस्तुत किये जा सके थे।

93/8572

DC. (F.T.)
24/04/23

234

ज.सि. नदीवय
के संशोधन
रखें

fedha
28/04/23
DC(F.T.)

webster
mishra

किन्तु जब यह सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तब वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकी तथा इन्हीं सिद्धान्त के आधार पर विभाग की रिव्यू याचिका सं०-243/2021 निर्णीत हुयी है। इस निर्णय का उल्लेख बिन्दु संख्या-02 में किया जा रहा है।

(02)-मारकण्डेय सिंह व अन्य 11 के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.03.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका महत्वपूर्ण एवं प्रभावी अंश है:-

"23. A perusal of judgment under review shows that each and every aspect of the matter has been considered and thereafter, the Special Appeal in question has been decided. There appears no apparent mistake in the judgment under review. Neither review court can examine the merit of the judgment as an appellate court nor in the garb of review petition, re-hearing of the matter cannot be permitted by this Court.

24. Consequently, in the facts of the present case and considering the facts and circumstances as well as financial implications, it is hereby provided that the judgement of learned Single Judge affirmed by the Division Bench will hold good for the writ petitioners only and will not be considered as a judgement in rem nor a binding precedent as the issues involved is left open to be decided in an appropriate case and all the questions of law are left open to be agitated by the State Government in the appropriate case.

25. Accordingly, the present review application is disposed of."

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निर्णय की प्रभाव-सीमा मारकण्डेय सिंह व अन्य 11 संग्रह अमीनों तक ही सीमित रहेगी। अन्य अमीनों के प्रकरण में उ०प्र० सरकार पर यह आदेश बाध्यकारी नहीं होगा, दृष्टांत नहीं बनेगा।

मा० उच्च न्यायालय का उक्त आदेश विभाग एवं राज्य सरकार को स्वीकार है, और उक्त के आलोक में ही प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाना वैधानिक बाध्यता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक-16.03.2023 के आलोक में प्रत्यावेदन का अविलम्ब निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

1. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.11.2019 की प्रति।
2. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू याचिका सं०-243/2021 में पारित आदेश की प्रति।
3. मुख्यालय के पत्र सं०-1054 दिनांक-31.03.2023 की प्रति।
4. राजस्व विभाग के पत्र सं०-15 दिनांक-24.01.2020 की प्रति।
5. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.03.2023 की प्रति।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि-पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

1. विशेष सचिव राज्य कर, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में प्राप्त होने वाले संग्रह अमीनों के प्रत्यावेदन के निस्तारण में उपर्युक्त मानको का समावेश किया जाना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक),.....सम्भाग....., राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में प्राप्त होने वाले संग्रह अमीनों के प्रत्यावेदन के निस्तारण में उपर्युक्त मानको का समावेश किया जाना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर
उ०प्र०, लखनऊ।

समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- मारकण्डेय सिंह व 11 अन्य व्यापार कर, वाराणसी के समतुल्य अन्य संग्रह अमीनों द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक-06.11.2019 व स्पेशल अपील के संबंध में पारित निर्णय दिनांक-02.12.2020 के अनुसार राजस्व संग्रह अमीनों की भांति उच्चकृत वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड व पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका सं०-243/2021 में अधोलिखित प्रकार से आदेश दिया गया है:-

"23. A perusal of judgment under review shows that each and every aspect of the matter has been considered and thereafter, the Special Appeal in question has been decided. There appears no apparent mistake in the judgment under review. Neither review court can examine the merit of the judgment as an appellate court nor in the garb of review petition, re-hearing of the matter cannot be permitted by this Court.

24. Consequently, in the facts of the present case and considering the facts and circumstances as well as financial implications, it is hereby provided that the judgement of learned Single Judge affirmed by the Division Bench will hold good for the writ petitioners only and will not be considered as a judgement in rem nor a binding precedent as the issues involved is left open to be decided in an appropriate case and all the questions of law are left open to be agitated by the State Government in the appropriate case.

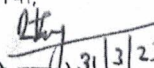
25. Accordingly, the present review application is disposed of."

यद्यपि मा० उच्च न्यायालय द्वारा मारकण्डेय सिंह व अन्य 11 याचीगणों को लाभ अनुमन्य किया गया है, किन्तु साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य प्रकरणों के लिये यह निर्णय किसी भी प्रकार बाध्यकारी दृष्टांत नहीं बनेगा।

भविष्य में संग्रह अमीनों के एतदर्थ प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश तथा इस पत्र के साथ संलग्न राजस्व परिषद के पत्र व वित्त आयोग की टिप्पणी में दिये गये तथ्यों को समावेशित करने के उपरान्त ही प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाये।

एतदर्थ समस्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण में उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(मिनिस्ती एस०) 31/3/23
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Reserved

Court-No. - 31

Case :- WRIT - A No. - 19438 of 2008

Petitioner :- Markandey Singh And Others

Respondent :- State Of U.P. And Others

Petitioner Counsel :- D.S.M, Tripathi

Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel, J.

Petitioners are 12 in number. They were Collection Amins in Revenue Department. They have preferred this writ petition for issuance of a writ of certiorari to quash the order dated 06.02.2008 passed by Joint Commissioner (Karya Palak), Trade Tax Varanasi, respondent no. 4 herein whereby he has rejected the representation of the petitioners for grant of promotional pay scale, second promotional pay scale and second selection grade as it was admissible to the Collection Amins of Revenue Department.

A further direction for a writ of mandamus/direction has been sought to be issued to the District Magistrate for grant of aforesated benefits.

Only material facts which are necessary to dispose of this writ petition are recapitulated herein:

All the petitioners were appointed as Collection Amins under the control of District Magistrate Varanasi in or around January & February 1977-78. They were stated to be appointed on regular basis against sanctioned posts. Their service conditions were governed under the Provisions of U.P. Collection Amin Service Rules, 1974 (hereinafter referred to as 'the Rules') and they were working in the Revenue

Department in District Varanasi. Their services were confirmed by the District Magistrate vide order dated 03.03.1986. The said order is Annexure-1 to the writ petition and it contains name of 108 Collection Amins. The name of the petitioners are in the said list.

It is stated that after the creation of Sales Tax Department, Collection Amins of Revenue Department, Naib Tehsildars and one Deputy Collector were sent on deputation in Sales Tax Department from time to time. All the petitioners were also sent on deputation in the Sales Tax Department. Before March, 1995 some of them got promotion also on the post of Naib Tehsildar in their parent Department while they were on the deputation in the borrowing Department viz Sales Tax Department.

It is stated that on 17.10.1985, a Government Order was issued giving the pay scale of Naib Tehsildar to all the Collection Amins. The said Government Order is Annexure-2 to the writ petition. Clause-III & Clause-IV of the said Government Order are important for the purpose of the issue involved in the present writ petition.

Clause-III of the Government Order provides that if an employee has completed 16 years of service including 6 years in selection grade and his service records are satisfactory, he shall be entitled for promotional grade. It was further provided that if there was promotional post then the pay scale of such Collection Amins shall be fixed on the basis of salary of the said post. In case no promotional post is available

then for those employees higher pay scale be given.

The petitioners' case is that all of them have already completed 10 years satisfactory service in or around 1987. The District Magistrate has sanctioned selection grade to all the petitioners. It is further stated that all the petitioners had completed in fact 16 years of service including 6 years of selection grade as back in the year 1993 and one of the petitioner in 1994. The details of completion of years of the petitioners of 10 years, 14 years, 19 years & 24 years have been mentioned in paragraph 13 of the writ petition in a tabular chart. The petitioners state that they had completed requisite 16 years service including 6 years of selection grade as in the year 1993-94 and as such they were entitled for the promotional pay scale in the year 1993-94. However, the District Magistrate did not sanction the promotional pay scale in terms of the Government Order dated 17.10.1985.

Their further case is that as petitioners were on deputation in the Sales Tax Department, the District Magistrate was the Competent Authority in their parent Department failed to issue necessary orders for their promotional pay scale. However, the Collection Amins working in the parent Department viz Revenue Department were sanctioned promotional grade in terms of the said Government Order and as such the petitioners were discriminated by the District Magistrate.

It is stated that the Government order dated 17.10.1985 was modified by Government Order dated

12.04.1990 whereby the pay scale of the Collection Amins were sought to be reduced and direction was issued to recover the excess amount which was paid to the Collection Amins on account of wrong fixation as the Government Order dated 17.10.1985 was appears to be misconstrued by the concerned Authority.

The said Government Order was challenged by the Union of the Collection Amins of Uttar Pradesh as well as by some new Collection Amins by way of Writ Petition No. 5763 (S/S) of 1998 Kanhaiya Lal & Others Vs. The State of U.P. & Others Connected with Writ Petition No. 4964 (S/S) of 1990 (Uttar Pradesh Rajasva Sangrah Karmchari Sangh through its General Secretary Vs. The State of U.P. & Others) And Writ Petition No. 5067 (S/S) of 1990 (Virendra Pratap Singh & Others Vs. The State of U.P. & Others).

In all these writ petitions as stated above, the Government Order dated 12.04.1990 was challenged for a direction that the alleged excess payment on the ground of wrong pay fixation of their salary cannot be made. The said writ petitions were allowed by a common judgement dated 09.08.2000 and a direction was issued that Collection Amins are entitled to get salary to the pay scale of Rs. 1400-2300. A copy of the said judgement is on the record as Annexure-3 to the writ petition.

Dissatisfied with the order of this Court dated 09.08.2000 in above mentioned writ petitions, an Special Appeal No. 83 of 2001 (SB) (The State of Uttar Pradesh & Others Vs. Kanhaiya Lal & Others) was filed.

However, no interim order was granted in the said appeal.

In compliance of the said judgement of this Court, the State Government issued a Government Order dated 27.03.2006 whereby the promotional pay scale i.e. Rs. 1400-2300 was sanctioned to the Collection Amins subject to the final decision of the aforesaid Special Appeal.

It appears that in pursuance of the said Government Order, some directions were also issued on administrative side and the Collection Amins who were working in the Revenue Department were granted the promotional pay scale as mentioned above. The petitioners were not granted the said benefit as they were on the deputation. The petitioners made representations separately to the District Magistrate for extending the benefit of the said Government Order dated 27.03.2006 to them w.e.f. 1993 as they had completed their 16 years continuous service. However, the petitioners were informed that that as they have already been absorbed in the Trade Tax Department under the provisions of U.P. Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995 (hereinafter referred to as 'the Rules 1995'), in terms of Rule 18(3) of the said Rules, the petitioners were found not getting benefit of Government Order dated 27.03.2006 and the judgement of this Court dated 09.08.2000 *inter alia* on the ground that they have not been absorbed in the Sales Tax Department in terms of Rule 18 sub Clause (3) of the Rules 1995 as they did not give any option

for their absorption and as such they remained on deputation in the borrowing Department and their parent Department continued to be Revenue Department.

Alternatively, petitioners took plea that the U.P. Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995 was framed in the year 1995 and they had become entitled for the promotional pay scale in the year 1993-94 prior to the framing of the said Rules of 1995 and as such there would be no effect of Rule 1983 in respect of their entitlement of the promotional pay scale.

Learned counsel for the petitioners has submitted that on the representation of the petitioners, the Additional Commissioner, Grade-I, Trade Tax, Varanasi Region Varanasi has made a strong recommendation to the Commissioner of U.P., Lucknow on 05.06.2007 for giving the benefit of promotional pay scale and non promotional pay scale after completion of 16 years and 24 years respectively by the petitioners. A copy of the said recommendation is Annexure-10 to the writ petition. The petitioner had also brought the judgement dated 09.08.2000 of this Court to the notice of District Magistrate who is the Competent Authority. However, on his turn, he instead of taking the decision himself sent the communication dated 12.12.2007 to the Joint Commissioner, Trade Tax, Varanasi for taking appropriate decision. It is stated that Joint Commissioner, respondent no. 4 by impugned order dated 06.02.2008 without giving any opportunity or notice to the petitioners has rejected the

representations of the petitioners by the order dated 06.03.2008 which has been impugned by the petitioners in the writ petition.

Respondents have filed a counter affidavit wherein they have taken a stand that the services of the petitioners in Trade Tax Department are government U.P. Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995. Whether they were appointed on or before 29.03.1995 are prior to that date. It was disputed that U.P. Collection Amin Service Rules, 1974 are applicable to the petitioners. The Amins working in the Trade Tax Department seized to be Amins to the Revenue Department w.e.f. 29.03.1995 when U.P. Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995 came into force ; Government Order dated 27.03.2006 (Annexure-4 to the writ petition) was not directed to Trade Tax Department. Therefore, the said Government Order in question was not applicable to the Amins working in Trade Tax Department as they were governed by a different set of service rules ; Rule 81(1) of Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995, services of all the Collection Amins of the Revenue Department working in the Trade Tax Department automatically absorbed in the Trade Tax Department and they seized in the service of Revenue Department from the date of notification dated 29.03.2005 which came into force on 29.03.1995.

The fact that Om Prakash Singh, one of the Collection Amin who was granted the benefit of the first promotional scale has been stated to be suffered from

an error which is being investigated.

I have heard Sri D.S.M. Tripathi, learned counsel for the petitioner and learned standing counsel for the respondents.

It is a common ground that all the petitioners were working as Collection Amins in the Revenue Department and their services were confirmed by the District Magistrate. They were sent on deputation in Trade Tax Department after the creation of the said Department.

The petitioners' parent Department remained the revenue Department. The Sales Tax Department was borrowing Department. All the petitioners had completed their 10 years of service in 1987-1988, 14 years of service in 1991-92, 19 years of service in 1996-97 & 24 years of service in 2001-2002. The said fact has been stated by the petitioner in paragraph 13 to the writ petition. The said statement of fact has not been denied in paragraph 10 of the counter affidavit.

The issue with regard to their entitlement for their next promotional post was set at rest by this Court in Writ Petition No. 5763 (S/S) of 1998 and connected writ petitions. There is nothing on record that the said order has been set aside in the special appeal as the said issue has already been decided by this Court in the aforesaid writ petition.

The only issue needs to be determination in this writ petition is whether the petitioners have completed the requisite number of years prior to 1995 Rules when

the new rules of U.P. Trade Tax Collection Amin Service Rules, 1995 was enforced.

From the perusal of the chart mentioned in paragraph 13 to the writ petition, it is manifestly clear that the petitioners were entitled for the promotional pay scale, second promotional pay scale prior to 1995 as they have completed 10 years in 1987, 14 years in 1991.

It is trite law that a deputationist continued to be employee of his parent Department and he remains substantively attached to the parent Department as he continued to hold the lien in the parent Department and he is entitled for promotion and seniority in his parent Department.

A constitution Bench of Supreme Court in the case of **State of Mysore Vs. M.H. Bellary AIR 1965 SC 868** has held that the officers on deputation remains the employee of the parent Department and entitled for the benefit of promotion as well as of seniority in his parent Department and there cannot be any automatic absorption in the borrowing Department. A deputationist has not right to be absorbed in the borrowing department automatically. His absorption in substantive capacity may be made only with his consent but petitioners have stated in their writ petition that they did not exercise any option for their absorption in the borrowing Department. The said fact has not been denied in the counter affidavit by respondent no. 4. The only reason given for rejection of their representation is that after framing 1995 Rules,

the services of the petitioners 'would be deemed to be absorbed and they would be treated to be substantively appointed in the Sales Tax Department.'

The said reason is incorrect and illegal inasmuch as all the petitioners are deputationists in the borrowing Department and without their consent they cannot be deemed to be absorbed in terms of Rule 18 of 1995 Rules.

It is also stated by the petitioners that the impugned order has been passed without giving any notice or opportunity. The said averments made by the petitioners in paragraph 41 has not been denied in the counter affidavit. Paragraph 41 of the writ petition and paragraph 27, reply of said para are extracted herein below:

41. "That without giving any notice and opportunity of hearing to the petitioner as well as without considering various Govt. Orders as well as judgement of High Court dated 09.08.2000 and G.O. Dated 27.03.2006, the respondent Joint Commissioner/respondent no. 4 acting against the law an in most arbitrary manner, has passed the order on 06.02.2008 rejecting the claim of petitioner on irrelevant and erroneous consideration by common reason in respect of all the petitioners."

27. "That the contents of the paragraph no. 41 of the writ petition are not admitted as stated. Representations were decided after careful consideration of relevant Govt. orders and facts of each individual case."

The impugned order has caused serious prejudice to the petitioners as they have denied first promotional pay scale and second selection grade from the various dates. The order suffers from violation of principles of natural justice as indisputably the petitioners have not been given any notice or opportunity.

It is well settled law that if any order is passed against a person which caused prejudice to a person, opportunity ought to have been given to such person before passing the order.

After careful consideration of the submissions of learned counsel for the parties and perusal of record, I am of the view that the impugned orders are liable to be set aside. The respondent no. 4 has passed separate orders in respect of the petitioners which have been collectively enclosed along with the writ petition as Annexure No. 15 to the writ petition. All the orders against the petitioners passed separately are quashed.

A direction is issued upon the respondent no. 4 to give notice and opportunity to the petitioners/their representatives and pass fresh order in the light and observations made herein above.

The writ petition is allowed.

No order as to costs.

Order Date :- 15.01.2013
Sandeep

Chief Justice's Court

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 756 of 2020

Appellant :- State Of U.P. And 3 Others

Respondent :- Markandey Singh And 11 Others

Counsel for Appellant :- Anand Kumar Ray

Counsel for Respondent :- Ashutosh Mani Tripathi, Durgesh Kumar Singh

Hon'ble Govind Mathur, Chief Justice

Hon'ble Piyush Agrawal, J.

This appeal is before us to examine correctness of the judgment dated 6th November, 2019 passed by learned single Bench in Writ-A No.23780 of 2014.

In brief factual matrix of the case is that the respondent-petitioners no.1 to 11 entered in service of the State of Uttar Pradesh being appointed as Revenue Collection Amins in the year 1977. The respondent-petitioner no.12 came to be appointed on the same post in the year 1978. The services of the respondent-petitioners at the first instance were placed at the disposal of Trade Tax Department on deputation but subsequently, on introduction of Uttar Pradesh Trade Tax Collection Amins Service Rules, 1995, the services of all the respondent-petitioners came to be absorbed in Trade Tax department as Trade Tax Collection Amins.

Suffice to state that as per Rule 18(1) of the Rules of 1995 any Collection Amin who has been appointed on or before 1st January, 1975 who has joined as Trade Tax Collection Amin w.e.f. 29th March, 1995 will be treated as having been absorbed in Trade Tax Department and will be deemed to have been appointed as Trade Tax Collection Amin and his services in revenue department will come to an end (forfeited) with effect from the date of his appointment in Trade Tax Department. Though, sub-Rule (1) refers for forfeiture of past services but the same are protected under sub-Rule (3) of Rule 18 of the Rules of 1995 that prescribes that the previous service of absorbed Collection Amin of Trade Tax Department will not be forfeited and the provisions of any rule, regulation or orders to the contrary shall stand relaxed.

It would also be appropriate to state that as per sub-Rule (2) of Rule 18, if any Collection Amin does not want to be absorbed in Trade Tax Department then he had an option to submit written objections to the Appointing Authority then a period of three months with regard to his unwillingness to be absorbed in the trade tax department and to continue with revenue department.

Before proceeding further, it would also be appropriate to state that the Government of Uttar Pradesh with a view to remove stagnation in service due to non-availability of adequate promotion avenues introduced a policy for grant of promotional scale, selection scale and grades at a definite interval of time. The policy aforesaid dated 17th October, 1985 prescribes for selection scale on completion of 10 years of service, which was subsequently, reduced to 8 years

of service. The grant of promotional post scale on completion of 16 years of service, which was subsequently, reduced to 14 years of service and further the grant of increment in promotional scale of 19 years of service. The respondent-petitioners claimed for grant of selection scale as well as promotional scale in accordance with circular dated 17th October, 1985. Being failed to have the same, they approached this Court by way of filing a petition for writ that came to be disposed of on 15th January, 2013. Learned writ Court disposed of the writ petition with a direction to pass appropriate orders by keeping in mind certain observations made by the Court. After disposal of the writ petition, the respondent-petitioners submitted detailed representations to the appellant-respondent and that came to be disposed of by different orders pertaining to each respondent-petitioner by the competent authority on 25th March, 2014.

For convenience, we have looked into the order relating to the respondent-petitioner Sri Markandey Singh, a retired Collection Amin. The competent authority rejected claim of the employees including Sri Markandey Singh by arriving at a conclusion that being difference in service conditions of Revenue Collection Amins and the Trade Tax Department Collection Amins, it would not be appropriate to grant the first promotional scale on completion of 16 years of service in the pay scale of Rs.1640-2900/-. The competent authority also noticed that the benefit of one additional increment on completion of 19 years of service and 24 years of service was already accorded to the respondent-petitioners. Being aggrieved by the decision of the competent authority, the respondent-petitioners preferred a petition for writ that came to be accepted under the judgment impugned dated 6th November, 2019.

In appeal, the argument advanced by learned Standing Counsel appearing on behalf of the appellant is that learned single Bench failed to appreciate that as per Rule 18(1) of the Rules of 1995, the respondent-petitioners could not have availed any benefit for the service rendered prior to their absorption in Trade Tax Department as Collection Amins. It is further stated that the service conditions of the post of Revenue Collection Amins and the Collection Amins working in Trade Tax Department being different, no benefit relating to grant of selection grade and promotional scale could have been allowed.

On going through the provisions of the Rules of 1995, we do not find any merit in the argument advanced.

It is not in dispute that the respondent-petitioners were working in revenue department in substantive capacity since 1977 and 1978. While holding the post of Collection Amin in revenue department they became entitled to have selection grade as well as promotional scale as per the order dated 17th October, 1985. For the reasons best known to the appellant-respondent, the benefits under the circular aforesaid were not extended to the respondent-petitioners.

Be that as it may, the right already accrued could have not been denied merely on the count that in the year 1995 all the respondent-petitioners came to be absorbed in service of the trade tax department under Uttar Pradesh Trade Tax Collection Amins Service Rules, 1995. The appellant-respondent has bent upon

its contention and provisions of Rule 18 of the Rules aforesaid but that is of no consequence.

Rule 18(3) of the Rules of 1995 in one specific terms provides that the services rendered by the absorbed Collection Amins shall not be forfeited and any restriction in that regard by any means including rules, regulations and orders shall stand relaxed.

In light of this provision, the absorption of the respondent-petitioners in trade tax department includes the previous services rendered by them in revenue department as Collection Amin. This period as such is required to be taken into consideration for grant of all service benefits including the benefits accrued as a consequence of the Circular dated 17th October, 1985. The rights so accrued could have not been denied by the appellant-respondent by ignoring provisions of sub-Rule (3) of Rule 18 of the Rules of 1995.

In view of whatever stated above, we do not find any error on part of learned single Bench that may warrant interference by us in appellate jurisdiction.

The appeal hence, is dismissed being bereft of merit.

Order Date :- 2.12.2020

Bhaskar

(Piyush Agrawal, J.) (Govind Mathur, C.J.)

गार्ड फाइल

ई-मेल / सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग-2, लखनऊ।

सेवा में,

1-समस्त माण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 2110/15/2-संग्रह-01सी/2020

दिनांक 24 जनवरी 2020

विषय- संग्रह अमीनों द्वारा प्रथम पदोन्नति वेतनमान के रूप में नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान एवं 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में तहसीलदार के पद का वेतनमान व 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए०सी०पी का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं एवं अवमानना याचिकाओं में प्रतिवाद किये जाने के संबंध में।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्राप्त शासन के पत्र संख्या- 853/एक-7-2019 - रा-7 दिनांक 13 जनवरी, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में निम्न निर्देश/तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

.....प्रदेश के विभिन्न जनपदों के संग्रह अमीनों द्वारा 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान रू० 8000-13500 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए०सी०पी का लाभ प्राप्त करने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में अत्याधिक संख्या में रिट याचिकाएँ एवं अवमानना याचिकाएँ उक्त अनुतोष मा० न्यायालय के माध्यम से भ्रांति किये जाने हेतु निरन्तर योजित हो रही हैं, जिसमें सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ राजस्व परिषद तथा शासन को प्रतिवादी बनाया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी शासन के संज्ञान में आया है कि रिट याचिकाओं में जनपद स्तर से लगाये जा रहे प्रतिशपथ-पत्रों में प्रतिवाद के रूप में सम्यक आधारों को नहीं लिया जा रहा है, जिससे अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त प्रकरण की उक्त पृष्ठभूमि में अवगत कराना है कि है कि याचियों द्वारा जिस शासनादेश दिनांक 24.07.2018 के आधार पर 24 वर्ष की सेवा (16.08.2003 को) पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान रू० 8000-13500 की मांग की गयी है, उक्त शासनादेश (दिनांक 24.07.2018), रिट याचिका संख्या-3059(एस०एस०)/2015 "जय नारायण यादव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 का अनुपालन न होने पर योजित अवमाननावाद संख्या-1924(सी०)/2015 "जय नारायण यादव व अन्य बनाम श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग व अन्य" में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 एवं अन्य के अनुपालन के दृष्टिगत किया गया है, ताकि अवमानना से बचा जा सके। मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के मूल में विशेष अपील संख्या-83/2001 "उ०प्र० राज्य थू प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग बनाम कन्हैया लाल व 10 अन्य" में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक 29.08.2014 को अंतिम रूप से पारित निर्णय है।

3- अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा प्रकरण में की गयी संवीक्षा एवं दिये गये परामर्श में यह स्पष्ट किया गया कि मा० न्यायालय के समक्ष सही तथ्य एवं कानूनी स्थिति प्रस्तुत न किये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा राजस्व परिषद के परिपत्र दिनांक 23.01.1989 (जिसमें संग्रह अमीनों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के पश्चात प्रोन्नती का अगला वेतनमान नायब तहसीलदार के पद का साधारण वेतनमान रू० 515 से 650 देय होगा।) को शासनादेश मानकर उसकी गलत

व्याख्या किये जाने तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1450/दस-85-स0व्य0(सा0)-82, दिनांक 06.11.1985 (जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि वस्तुतः दिनांक 06.11.1985 से अगले वेतनमान/पदोन्नत वेतनमान की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान अवश्य हुआ है परन्तु संग्रह अमीन इस शासनादेश से आच्छादित नहीं है क्योंकि न तो उन्हें दिनांक 17.10.1985 तक निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों में सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किया गया है और न ही उनको विभागीय शासनादेश द्वारा अनुमन्य किया गया है।) की भी गलत व्याख्या किये जाने सहित वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1763/दस-39-(एम0)/89, दिनांक 03.06.1989 के क्रम में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-6434/939डी-7/89-रा0-7, दिनांक 12.04.1990 का भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एकीकृत संग्रह योजना के अंतर्गत कार्यरत संग्रह अमीनों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की 06 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अगला वेतनमान रू0 975-1600 देय होगा। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा "Subordinate Revenue Executive Service (Naib Tehsilildars) Rules, 1944" के नियम-5 के अनुसार संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का अवसर उपलब्ध होने के आधार पर संग्रह अमीनों को वेतनमान (रू0 1400-2300) के आधार पर वेतन दिये जाने हेतु उपयुक्त पाया, जबकि उक्त नियमावली-1944 नायब तहसीलदार सेवा संवर्ग के लिये है, और नियमावली का नियम-5 नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती के स्रोत से सम्बन्धित है। उक्त व्यवस्था चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जिसका संग्रह अमीनों को समयमान/पदोन्नति वेतनमान दिये जाने से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार संग्रह अमीन के पद पर सेलेक्शन ग्रेड की 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा के आधार पर पदोन्नति के अगले पद (नायब तहसीलदार) के हेतु प्रथम पदोन्नति वेतनमान रू0 1400-2300/1640-2900 (पुनरोक्षित वेतनमान रू0 5500-9000) दिये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संग्रह कर्मचारी संघ, वीरेन्द्र प्रताप सिंह व कन्हैया लाल द्वारा मा0 न्यायालय को गुमराह कर अलग-अलग योजित 03 रिट याचिकाओं (1-रिट याचिका संख्या-4964 (एस0एस0)/1990 "उ0प्र0 राजस्व संग्रह कर्मचारी संघ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य", 2-रिट याचिका संख्या-5067(एस0एस0)/1990 "वीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" एवं 3-रिट याचिका संख्या-5763(एस0एस0)/1998 "कन्हैया लाल, बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य") में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ सुनवाई कर दिनांक 09.08.2000 को पारित किये गये निर्णय में अनेक कानूनी त्रुटियाँ हुई हैं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 और 29 अगस्त, 2014 का इस प्रकार से प्रतिवाद किया जाय, जिससे इसका प्रभाव संग्रह अमीनों के अन्य किसी भी प्रकरण पर पड़ने की सम्भावना न रह जाय। यह उल्लेखनीय है कि प्र इनगत आदेश केवल कुल 11 संग्रह अमीनों के संदर्भ में थे। इसी क्रम उक्त निर्णय दिनांक 09.08.2000 के विरुद्ध योजित विशेष अपील 83/2001 "उ0प्र0 राज्य शू प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग बनाम कन्हैया लाल व 10 अन्य" में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैच लखनऊ द्वारा दिनांक 29.08.2014 में भी उक्त कानूनी त्रुटियाँ विद्यमान हैं। उक्त के दृष्टिगत वित्त विभाग के परामर्श/संवीक्षा के क्रम में उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2014 के विरुद्ध निम्न आधारों पर पुनर्विचार याचिका योजित किये जाने का मत स्थिर किया गया है:-

- (1) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जन्मपदों में संग्रह अमीनों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हुये सर्वप्रथम अधिसूचना दिनांक 09.08.1974 से उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 बनायी गयी। उक्त नियमावली के अनुसार संग्रह अमीन (साधारण वेतनमान) का पद सीधी भर्ती का पद था, जिसके लिये दिनांक 01.08.1972 से वेतनमान रू0 200-320 नियत किया गया था तथा संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) पदोन्नति का पद था, जिसके लिये दिनांक 01.08.1972 से रू0 230-380 नियत किया गया था।

(3)

- (2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.1986 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के पूर्व कतिपय शासनादेशों से कतिपय पदों हेतु एक निश्चित सेवा अवधि पर वैयक्तिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इसी क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.10.1985 में यह प्राविधान किया गया था कि इस शासनादेश में उल्लिखित विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जिन पदों के लिये वैयक्तिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान स्वीकृत किया गया हो उनके पदधारकों को सेलेक्शन ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पर या तो पदोन्नत का अगला वेतनमान अनुमन्य कर दिया जाय अथवा यदि पदोन्नत का पद न हो तो अगला उच्च वेतनमान अनुमन्य किया जाय।
- (3) इसी प्रकार वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 06.11.1985 से यह आदेश निर्गत किये गये थे कि शासनादेश दिनांक 17.10.1985 के अतिरिक्त जिन कतिपय अन्य पदों/संवर्गों में नियुक्त राजकीय कर्मचारियों को किसी अन्य शासनादेश से भी समयमान वेतनमान के रूप में सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान की सुविधा वैयक्तिक रूप से प्रदान की जा चुकी है, उन्हें भी कुल 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 06 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में अनिवार्य है, संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से प्रदान किया जायेगा।
- (4) उक्त शासनादेश दिनांक 17.10.1985 एवं दिनांक 06.11.1985 के पश्चात् दिनांक 01.01.1986 से लागू चतुर्थ वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 03.06.1989 में पहली बार एक निश्चित मूल वेतन (जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन रु० 3500 हो) तक के सभी कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान एवं वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था लागू की गयी।
- (5) संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 से यह स्पष्ट है कि संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली में संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) नामक एक पद था, जो संग्रह अमीन (साधारण वेतनमान) के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता था। नियमावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें कुल 5341 पद संग्रह अमीन (साधारण वेतनमान) के पद थे तथा कुल 593 पद संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) के। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संग्रह अमीनों को न शासनादेश दिनांक 17.10.1985 में उल्लिखित किसी शासनादेश से न ही किसी अन्य विभागीय शासनादेश से कभी भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किये जाने वाला सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान अनुमन्य/स्वीकृत नहीं किया गया था। अस्तु संग्रह अमीन न तो शासनादेश दिनांक 17.10.1985 से व्यवस्था से आच्छादित थे, न ही शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 1985 की व्यवस्था से।
- (6) उक्त से स्पष्ट है कि संग्रह अमीन पद हेतु दिनांक 01.01.1986 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 03.06.1989 के अनुसार ही पहली बार समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य हुआ।
- (7) उक्त तथ्य के बावजूद राजस्व परिषद द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 23.01.1989 प्रेषित किया गया। इस पत्र में यह कहा गया कि कदाचित्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.10.1985 तथा दिनांक 06.11.1985 के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही होगी और चूंकि शासनादेश दिनांक 06.11.1985 में यह कहा गया है कि ऐसे पदधारक जो सम्बन्धित पद पर नियमित हैं और जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 06 वर्ष की सेवा सेलेक्शन ग्रेड में अनिवार्य है, संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया जाना है और इस शासनादेश के प्रस्ताव-4 के अनुसार यह स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से की जानी है, अतः सभी जिलाधिकारी उक्त शासनादेश में निहित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर परिषद को उपलब्ध कराये। इसी पत्र के प्रस्ताव-3 में यह भी त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया कि संग्रह अमीनों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के पश्चात् प्रोन्नति का अगला वेतनमान नायब तहसीलदार पद का साधारण वेतनमान रु० 515-860 है जबकि तथ्य यह रहा है कि दिनांक 01

जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के पूर्व संग्रह अमीनों को किसी भी शासनादेश से वैयक्तिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान अनुमन्य नहीं किया गया था। फिर उक्त वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पर अगला पदोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य किये जाने का कोई प्रश्न नहीं था। यह भी चढ़ी वृद्धि थी, जो संग्रह अमीनों के प्रथम पदोन्नति का पद नायब तहसीलदार का पद बताया गया क्योंकि स्वयं संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली में ही संग्रह अमीनों की पदोन्नति का पहला पद संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) निर्धारित था, जिसका आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।

- (8) राजस्व परिषद द्वारा जारी किए गए दिनांक 23 जनवरी, 1989 के परिपत्र को नियमानुकूल न पाते हुये राजस्व अनुभाग-7 के पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1990 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया कि शासनादेश दिनांक 03 जून, 1989 के प्रस्तर-10 के प्राविधानों के अनुसार एकीकृत संग्रह योजना के संग्रह अमीनों को सेलेक्शन ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अगला वेतनमान रू० 975-1600 ही देय होगा। वस्तुतः राजस्व अनुभाग-7 का यह पत्र पूरी तरह नियमानुसार था क्योंकि संग्रह अमीनों को दिनांक 01 जनवरी, 1986 के पूर्व किसी भी शासनादेश से कोई भी सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत नहीं हुआ था और उन्हें सेलेक्शन ग्रेड का वैयक्तिक रूप से कोई भी लाभ पहली बार शासनादेश दिनांक 03 जून, 1989 की व्यवस्थानुसार ही अनुमन्य होना था। इस शासनादेश में सेलेक्शन ग्रेड के रूप में सम्बन्धित पद पर 10 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य करायी जानी थी और पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर सम्बन्धित पद के पदोन्नति के पद का वेतनमान प्रथम वैयक्तिक पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में और यदि ऐसा पदोन्नति का न उपलब्ध हो तो पद के वेतनमान के अगले वेतनमान को प्रथम वैयक्तिक पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराया जाना था।
- (9) राजस्व अनुभाग-7 के उक्त आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 1990 के विरुद्ध प्रस्तर-2 में उल्लिखित 03 रिट याचिकाएँ योजित हुई। रिट याचिका संख्या-5763/1998 कन्हैया लाल बनाम राज्य सरकार, रिट याचिका संख्या-4964/1990 राजस्व संग्रह कर्मचारी संघ बनाम राज्य सरकार एवं रिट याचिका संख्या-5067/1990 वीरन्द्र प्रताप सिंह बनाम राज्य सरकार में याचिकाओं द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.10.1985 के प्रकाश में यह अनुतोष मांगा गया कि उन्हें संग्रह अमीन के पद पर सेलेक्शन ग्रेड में 06 वर्ष सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा के आधार पर पदोन्नति के अगले पद के वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराया जाय। इन रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुये मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.08.2000 द्वारा शासन के आदेश दिनांक 12.04.1990 को अपास्त कर दिया गया और यह आदेश दिया गया कि संग्रह अमीन शासनादेश दिनांक 17.10.1985 के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में वेतनमान रू० 1400-2300 का लाभ पाने के हकदार हैं।
- (10) मा० उच्च न्यायालय में जब उपर्युक्त संदर्भित तीनों रिट याचिकाओं को एकीकृत करते हुये सुनवाई की गयी तो अपने आदेश दिनांक 09.08.2000 में निम्न आधार लिये :-
- (i) राजस्व परिषद का पत्र दिनांक 23.01.1989 जिसमें यह कहा गया था कि संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान प्रथम पदोन्नति के वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया जायेगा।
 - (ii) शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 जिसके अनुसार यह प्राविधान किया गया था कि सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त 16 वर्षीय सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नत का अगला वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा।
 - (iii) सबऑर्डिनेट रिव्यू एक्जीक्यूटिव सर्विस (नायब तहसीलदार) रूल, 1944 का नियम-5, जिसमें नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती के स्रोतों में एक निश्चित प्रतिशत पद पर एक निश्चित अर्हता वाले संग्रह अमीनों से भरा जाना था।
 - (iv) वित्त विभाग का शासनादेश दिनांक 03 जून, 1989 जिसमें अधिकतम मूल वेतन रू० 3500 तक वालों के लिये यह प्राविधान किया गया था कि उन्हें सेलेक्शन ग्रेड में

06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगला पदोन्नतीय वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा।

(11) मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 के लिये उक्त जिन आधारों को लिया गया, वह निम्न कारणों से त्रुटिपूर्ण है:-

(i) राजस्व परिषद का पत्र दिनांक 23.01.1989 नियमों से परे था तथा अन्तिम भी नहीं था। इस पत्र में ही यह उल्लिखित है कि इस पत्र से मात्र सूचना एकत्र की जा रही थी तथा इस सूचना के आधार पर शासन से पत्राचारित आदेश प्राप्त किया जाना था क्योंकि इस पत्र में जिस शासनादेश दिनांक 17.10.1985 एवं शासनादेश दिनांक 06.11.1985 का हवाला दिया गया था, उनके बारे में यह कहा गया था कि उन शासनादेशों के अनुसार प्रोन्नत के अगले वेतनमान की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा विस्त विभाग की सहमति से की जानी है।

(ii) मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचीगणों से यह अपेक्षा नहीं की गयी कि उनके द्वारा उस शासनादेश को प्रस्तुत किया जाय, जिसके माध्यम से उन्हें शासनादेश दिनांक 17.10.1985 अथवा दिनांक 06 नवम्बर, 1985 का लाभ पाने के लिये कमी नी वैयक्तिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान स्वीकृत किया गया रहा हो। यह भी स्वीकार किया जाता है कि तत्समय शासन द्वारा लगाये गये प्रतिशपथ पत्र में याचीगणों के अभिकथन पर प्रतिवाद न किया जाना भी एक गम्भीर त्रुटि थी किन्तु इस प्रकार की त्रुटि का परिणाम चूंकि राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ रु० के व्ययभार के रूप में आना स्वाभाविक है। अतः सही स्थिति रखते हुये मा० उच्च न्यायालय के आदेशों पर पुनर्विचार कराये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय में रिट योजित किया जाना आवश्यक हो चुका है।

(iii) किसी भी पद के लिये पदोन्नतीय पद एवं उसका वेतनमान सर्वप्रथम सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अनुसार संग्रह अमीन (साधारण वेतनमान) के प्रथम पदोन्नत का पद संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) विद्यमान था। अस्तु ऐसी स्थिति में सबऑर्डिनेट रिवन्यू एक्जीक्यूटिव सर्विस (नायब तहसीलदार) रूल, 1944 के नियम-5 के आधार पर उनका प्रथम पदोन्नतीय पद नायब तहसीलदार नियत किया जाना एक गम्भीर त्रुटि थी। विभाग द्वारा इस तथ्य का प्रतिवाद किस रूप में किया गया, वह तो स्पष्ट नहीं है जो विभाग स्पष्ट कर लेंगे किन्तु शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 1990 से संग्रह अमीनों को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान के रूप में जो रु० 975-1660 देय होने का निर्णय लिया गया, वह सर्वथा नियमानुसार था।

(iv) यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संवर्ग के किसी पद का पदोन्नत का पद वह होता है, जिस पर वरिष्ठता क्रम में निचले पद के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के विचार क्षेत्र में रखा जाय और इस पदोन्नत से या तो अनुपयुक्त बंचित हो, या जिनकी सेवायें असंतोषजनक रही हों। नायब तहसीलदार की सेवा नियमावली में वरिष्ठता क्रम से सभी संग्रह अमीनों को पदोन्नत के लिये विचार किये जाने का प्राविधान ही नहीं है। इसके अलावा नायब तहसीलदार का पद संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संवर्गीय पद नहीं है अपितु यह एक भिन्न संवर्ग का पद है, जिस पर कुछ योग्यता रखने वाले संग्रह अमीन केवल एक निश्चित प्रतिशत तक इंटैक पाते हैं। मा० उच्च न्यायालय द्वारा संग्रह अमीनों का पदोन्नतीय पद नायब तहसीलदार का पद माने जाने में यह तथ्यात्मक त्रुटि हुई और केवल याचीगणों के कथन तथा राजस्व परिषद के त्रुटिपूर्ण पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1989 को संज्ञान में लेते हुये निर्णय दिया गया।

(v) प्रश्नगत तीनों रिट याचिकाओं में से एक रिट याचिका संख्या- 4964/1990 के परस्तर-9 में याची का अभिकथन असत्य है कि याची को बोर्ड ऑफ रिवन्यू के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1989 के अनुक्रम में नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया गया है। तथ्य यह है कि उक्त पत्र से केवल सूचना एकत्र की जानी थी और किस वेतनमान का प्रोन्नतीय वेतनमान स्वीकृत किया जाना था, यह निर्णय शासन स्तर पर होना था। यह बोर्ड ऑफ रिवन्यू के पत्र

दिनांक 23 जनवरी, 1989 में भी उल्लिखित है और शासन द्वारा लगाये गये प्रतिशपथ पत्र के प्रस्तर-9A में भी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक था।

- (12) राज्य सरकार द्वारा पुनः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या-83/2001 राज्य सरकार बनाम कन्हैया लाल और 10 अन्य योजित की गयी किन्तु विशेष अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए था, राज्य सरकार द्वारा उस बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट न कर एक अन्य प्रकरण अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03 अप्रैल, 1998 को आधार बनाया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया था कि संग्रह अमीनों को प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 1200-2040 ही अनुमन्य हो सकता है। विशेष अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्क को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव का प्रकरण गिन्न आधार पर लड़ा गया था। विशेष अपील ने यह माना गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव के प्रकरण में बोर्ड ऑफ रिबन्डू के आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1989 के आधार पर ए0डी0एम0 द्वारा संग्रह अमीन को स्वीकृत किये गये प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान रू0 1400-2300 को जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने के विरुद्ध याचनी द्वारा योजित रिट याचिका में विचार किया था जबकि आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील संख्या-83/2001 योजित की गयी में राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को चुनौती दी गयी थी। विशेष अपील इसी तकनीकी आधार पर निरस्त हो गई थी। इस प्रकार विशेष अपील में न तो राज्य सरकार द्वारा जो तथ्य रखे जाने थे वह रखे गये और न ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ही आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 के आधारों का परीक्षण किया जा सका।

- (13) यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील के आदेश दिनांक 29.08.2014 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-5908/2015 योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2015 को निम्नवत् आदेश दिया गया है :-

Delay condoned.

The Special leave petition is dismissed.

However, the question of law will be left over.

- (14) यद्यपि उक्त के पश्चात् आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 से आच्छादित कतिपय याचिकाओं को मा0 उच्च न्यायालय में योजित अद्यमानवाद की कार्यवाही की जायता में तदनुसार लाभ भुगतान कर दिये गये हैं किन्तु मा0 उच्च न्यायालय में ही सही तथ्यों के आधार पर समुचित रीति से प्रतिवाद किया जाना और समुचित प्रार्थना किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अन्यथा की स्थिति में इसका सबसे व्यापक प्रभाव यह पड़ सकता है कि अन्यान्य रिट याचिकाओं में पृथक-पृथक इन्हीं आदेशों के आधार पर लाभ अनुमन्य हो जाये और राज्य सरकार पर अनावश्यक व निघम विरुद्ध वित्तीय व्यय भार आयगा। अतः प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य जो ऊपर स्पष्ट किये गये हैं, उनके आधार पर कोई भी प्रतिवाद निम्न आधारों को भी संज्ञान में लेकर किया जाना शासकीय हित आवश्यक होगा:-

- (i) यह की संग्रह अमीनों की नियमावली, 1974 में ही उनके पदोन्नति का पद स्पष्ट है, इसमें प्रथम एवं अन्तिम पदोन्नति का पद संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) है।
- (ii) यह की संग्रह अमीनों को न ही शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 के अनुसार कोई लाभ मिलना है क्योंकि इस शासनादेश में उल्लिखित किसी भी शासनादेश द्वारा इन्हें कभी भी वैयक्तिक रूप से समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है

और न ही इन्हें शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 के क्रम में जारी शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 1985 के अनुसार कोई लाभ अनुमन्य होना है क्योंकि इन्हें अन्य किसी विभागीय शासनादेश से भी कोई संलेक्शन ग्रेड वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः किसी भी संग्रह अमीन को समवमान वेतनमान/वैयक्तिक पदोन्नतीय वेतनमान/ अगले वेतनमान का जो भी लाभ अनुमन्य हो सकता है वह मात्र शासनादेश दिनांक 03 जून, 1989 के प्रस्तर-3(9) एवं 3(10) के अनुसार। इस शासनादेश के प्रकाश में ऐसे संग्रह अमीन जिनकी दिनांक 01 जनवरी, 1986 को अथवा उसके पश्चात् किसी भी तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी हो उन्हें उस तिथि से संलेक्शन ग्रेड के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य हो सकता है। पुनः इन्हें उक्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा के पश्चात् ही प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान वैयक्तिक रूप से और यदि पदोन्नतीय वेतनमान उपलब्ध न हो तो अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो सकता है।

(iii) चूंकि संग्रह अमीनों की सेवा नियमावली में ही प्रथम पदोन्नतीय पद संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) है। अतः संग्रह अमीन (साधारण वेतनमान) के पदधारक का प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) के पद का वेतनमान ही अनुमन्य हो सकता है। इसी प्रकार संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) के पदधारक को उसके वेतनमान का अगला वेतनमान शासनादेश दिनांक 03 जून, 1989 के संदर्भ में प्रथम पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य हो सकता है।

(iv) यह कि किसी संग्रह अमीन (चयन वेतनमान) के पदधारकों को भी प्रथम पदोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान इसलिए नहीं अनुमन्य हो सकता क्योंकि इस पद का पदोन्नति का पद नायब तहसीलदार नहीं माना जा सकता। यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संवर्ग के किसी पद का पदोन्नत का पद वह होता है, जिस पर वरिष्ठता क्रम में निचले पद के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के विचार क्षेत्र में रखा जाय और इस पदोन्नत से था तो अनुपयुक्त चयित हो, या जिनकी सेवायें असंतोषजनक रही हों। नायब तहसीलदार की सेवा नियमावली में वरिष्ठता क्रम से सभी संग्रह अमीनों को पदोन्नत के लिये विचार किये जाने का प्राविधान ही नहीं है। इसके अलावा नायब तहसीलदार का पद संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संवर्गीय पद नहीं है अपितु यह एक भिन्न संवर्ग का पद है, जिस पर कुछ योग्यता रखने वाले संग्रह अमीन केवल एक निश्चित प्रतिशत तक इंडेक पाते हैं।

(v) राजस्व परिषद द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1989 से जो सूचना प्रसारित करायी गयी कि संग्रह अमीन पद का प्रथम पदोन्नति का पद नायब तहसीलदार है, नियमावली, 1974 की व्यवस्था से भिन्न होने के कारण पूर्णतया अनियमित है।

(vi) बोर्ड ऑफ रिवन्यू के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1989 के आदेश को आधिकारिक आदेश माने जाने का आधार लिया जाना न तो याचीगण के लिये सही था और नहीं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्योंकि इस आदेश में ही स्पष्ट रूप से कथित था कि शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 अथवा शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 1985 के क्रम में अगले पदोन्नतीय पद के वेतनमान का निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाना है। इतना ही नहीं राजस्व परिषद का पत्र मात्र एक सूचना संकलन विषयक पत्र था, यह कोई आदेश नहीं था। साथ ही राजस्व परिषद के पत्र में जो स्व स्तर से यह कहा गया कि संग्रह अमीनों को शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 या शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 1985 का लाभ अनुमन्य कराया जाना है, वह भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था क्योंकि संग्रह अमीन इन दोनों शासनादेशों की व्यवस्था से आच्छादित नहीं थे।

(8)

अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य को स्पष्ट करते हुये प्रतिवाद के आधार संकलित करते हुये इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि इन सभी तथ्यों को अक्षरशः प्रतिवाद के लिये संज्ञान में लिया जाय और मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 अगस्त, 2000 और 29 अगस्त, 2014 का इस प्रकार से प्रतिवाद किया जाय, जिससे इसका प्रभाव संग्रह अमीनों के अन्य किसी भी प्रकरण पर पड़ने की सम्भावना न रह जाय। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आदेश केवल कुल 11 संग्रह अमीनों के संदर्भ में थे। अतः किलहाल इन आदेशों को अन्य किसी प्रकरण पर लागू न माने जाय और यदि कोई याचिका अथवा अवमानना संज्ञित की जाती है तो उसका सम्यक् निस्तारण/प्रतिवाद किया जाय।

4- अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं एवं अवमाननावादों में याचीगणों के संबंध में नियमानुसार उनके सेवा अभिलेखों, राजस्व संग्रह अमीन के पद पर नियमित नियुक्ति एवं संग्रह अमीन के पद पर स्थाई किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत औपचारिक आदेशों की प्रामाणिकता/पुष्टि करते हुए याचीगणों की पात्रता का परीक्षण आपके स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाय।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 एवं 3 में वर्णित वस्तु-स्थिति एवं आधारों के संदर्भ में विषयगत प्रकरणों में अपने स्तर पर याचीगणों के प्रकरणों में देय लाभों की पात्रता का उपर्युक्तानुसार तथ्यात्मक/अभिलेखीय परीक्षण कराने के उपरान्त सम्यक् निस्तारण कर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य को स्पष्ट करते हुये प्रतिवाद के उपर्युक्त आधारों को अक्षरशः संकलित कर वस्तुस्थिति से मा० न्यायालय को अवगत कराने एवं प्रतिवाद/प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।
24.1.2023

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-7, लखनऊ को शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13-01-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे० बी० यादव)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

Case :- **CIVIL MISC REVIEW APPLICATION No.243 of 2021**

Applicant :- State Of U.P. and 3 others

Opposite Party :- Markandey Singh and 11 others

Counsel for Applicant :- Gopal Chandra Saxena, Apurva Hajela

Counsel for Opposite Party :- Durgesh Kumar Singh, Ashutosh Mani Tripathi, Daya Shanker Mani Tripathi

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi, J.

Hon'ble Piyush Agrawal, J.

1. Heard Sri Manish Goyal, learned Additional Advocate General assisted by Sri Apurva Hajela, learned Standing Counsel for the State of U.P./review applicants and Sri Ashutosh Mani Tripathi, learned counsel for the respondents-petitioners.

2. The present review application is preferred to review the judgment and order dated 02.12.2020 passed in Special Appeal No.756 of 2020 (State of U.P. and 3 others v. Markandey Singh and 11 others) whereby, the coordinate Bench of this Court had proceeded to dismiss the appeal with following observations:-

"It is not in dispute that the respondent-petitioners were working in revenue department in substantive capacity since 1977 and 1978. While holding the post of Collection Amin in revenue department they became entitled to have selection grade as well as promotional scale as per the order dated 17th October, 1985. For the reasons best known to the appellant-respondent, the benefits under the circular aforesaid were not extended to the respondent-petitioners.

Be that as it may, the right already accrued could have not been denied merely on the count that in the year 1995 all the respondent-petitioners came to be absorbed in service of the trade tax department under Uttar Pradesh Trade Tax Collection Amins Service Rules, 1995. The appellant-respondent has bent upon its contention and provisions of Rule 18 of the Rules aforesaid but that is of no consequence.

Rule 18(3) of the Rules of 1995 in one specific terms provides that the services rendered by the absorbed Collection Amins shall not be forfeited and any restriction in that regard by any means including rules, regulations and orders shall stand relaxed.

In light of this provision, the absorption of the respondent-petitioners in trade tax department includes the previous services rendered by them in revenue department as Collection Amin. This period as such is required to be taken into consideration for grant of all service benefits including the benefits accrued as a consequence of the Circular dated 17th October, 1985. The rights so accrued could have not been denied by the appellant-respondent by

ignoring provisions of sub-Rule (3) of Rule 18 of the Rules of 1995.

In view of whatever stated above, we do not find any error on part of learned single Bench that may warrant interference by us in appellate jurisdiction."

3. Learned Additional Advocate General, appearing for the applicants has vehemently contended that the respondent-petitioners were appointed as Revenue Collection Amins in the years 1977-78. They were sent to the Trade Tax Department on deputation but subsequently, on introduction of Uttar Pradesh Trade Tax Collection Amins Service Rules, 1995 (in short, Rules, 1995), they were absorbed in Trade Tax department. The impugned judgment has been passed only on the basis of the absorption of the respondents-petitioners in Trade Tax department as Trade Tax Collection Amins but it has not been decided whether the petitioners-respondents are entitled to promotional pay scale and other benefits before their absorption in Trade Tax Department in view of the Government Orders dated 17.10.1985 and 02.12.2000. It is not disputed that the petitioners were appointed in years 1977-78 and as such, the benefit of Government Order dated 17.10.1985 was not applicable to them as the aforesaid Government Order was valid till 31.12.1985 and till that date, the petitioners were not eligible for any selection grade under the aforesaid Government Order or any other Government Orders. He further submits that the system of Time Pay Scale was introduced w.e.f. 01.01.1986 by Government Orders dated 03.06.1989 and 02.12.2000 and all earlier Government Orders required at least a minimum period of 10 years of service for eligibility of selection grade and 16 years regular service was required for adding the selection grade for being eligible for first Assured Career Progression (A.C.P) but the petitioners did not complete 10 years service for entitlement of selection grade till 01.01.1986 and as such, the Government Order dated 17.10.1985 was not applicable to them and they were not entitled for any benefits in view of Government Order dated 17.10.1985.

4. Learned Additional Advocate General further submits that as per the Government Order dated 03.06.1989 the main ingredient for grant of pay scale was that the persons, who had already availed the benefit of selection grade, shall be entitled for the first ACP after 6 years counting the period of selection grade i.e. 16 years. Further, those employees, who have not received the selection grade, shall be entitled for it w.e.f. 01.01.1986 or after 10 years of regular service, whichever is later, and they shall be entitled for one increment in their Basic Pay Scale and shall be given the benefits of selection grade and thereafter, after 6 years they shall

be granted the first ACP. The petitioners fall under this second condition. In case the services of the petitioners are counted from year 1997 then after 10 years they are entitled for the selection grade with the benefits of one increment and after 16 years i.e. in year 1993 they shall be entitled for the benefits of first A.C.P., which is the first promotional pay scale under their earlier service Rules of Revenue Collection Amin. He further submits that since the services of the petitioners are governed by the Revenue Collection Amins Service Rules 1978 and as such, their pay scale for the post of collection Amin is Rs.975 - 1660/- (Basic Pay). During the year 1993, the petitioners were in drawing the basic pay scale of Rs.975 - 1660/- and after absorption in the Trade Tax Department in year 1995 after counting the past services of Revenue Department from 01.01.1996, their first ACP/revised pay scale is Rs.3200 - 4900/- and after 24 years of service the revised pay scale as per the Government Order dated 02.12.2020 is Rs. 4000 - 6000/-. Hence, after their absorption in the Trade Tax Department from year 1995 the petitioners are not entitled for a pay scale of Rs.5500 - 9000/- after completing of 16 years of service.

5. He further submits that the services rendered by the absorption of the Collection Amin shall not be forfeited under Rule 18(3) of Rules, 1995. However, it has to be seen that the pay scale admissible and to be paid to the aforesaid collection Amins shall be in accordance with Rule 18(3) of the Rules of the Trade Tax Department. The promotion and other service benefits shall be governed by the Rules and Regulations of the Trade Tax Department. He further submits that the benefits of Time Pay Scale or the option of the promotional benefits cannot be granted by adding the earlier services of the petitioners in the Revenue department after they had already been absorbed in the Trade Tax Department. He further submits that the date of absorption in the Trade Tax Department is to be considered as the substantive date for grant of future service benefits to the petitioners in accordance with the Trade Tax department Rules as per Rule 18(3) of the Rules. In other words, the petitioners after the absorption in the Trade Tax Department shall be given the promotional benefits and other service benefits as per the Rules governing their department only. Hence, for the purpose of promotional benefits, the services rendered by the petitioners in the Revenue Department cannot be taken into account. He further submits that the Hon'ble Court did not consider the applicability of the Government Order dated 17.10.1985 as the same was not applicable to the petitioners. While allowing the writ petition on 06.11.2019 learned Single

Judge had already held that the petitioners cannot be granted parity with the collection Amin working in the Revenue Department. Such a plea of grant of equal pay scale, the selection grade and promotional pay scale available to the collection Amins of the Revenue Department had been turned down by this Hon'ble Court in Special Appeal No. 1016 of 2013 (**State of U.P. and 3 others Versus Fateh Bahadur Singh and 6 others**). He lastly submits that after the absorption of the petitioners in Trade Tax Department in the year 1995 the future service benefits are to be paid in accordance with the Rules governing their department and the past services of petitioners in the Revenue Department cannot be taken into account and hence, the petitioners are not entitled for Time Pay Scale of Rs.5500 - 9000/-.

6. He lastly submits that the important question of law is involved in the matter as to whether the Government Order dated 17.10.1985 will be applicable to the employees, who stand absorbed in the services of Trade Tax Department in pursuance of Rules, 1995 after exercising their option under Rule 18 (2) and as such, will be governed by Rule 18 (1) of the Rules, 1995 and further whether the said Government order will be applicable on those employees, who have already been taken promotion either in parent department or after absorption and given pay scale to them will not create any right in them to claim further pay scale. He has vehemently submitted that whether purposive construction is to be given to Rule 18 of the Rules, 1995 and whether Rule 18 (1) is to be read harmoniously with Rule 18 (2) and 18 (3) of the Rules, 1995. He submits that the Rules framed under Article 309 of Constitution of India will override all Government orders, which are in nature of executive instructions and moreover, whether a vested right is created in favour of the employees of the Revenue Department to claim time scale of pay in terms of Government order dated 17.10.1985, once they stand absorbed in Trade Tax Department. Therefore, the judgment under review is apparently erroneous on the face of record. It is submitted that the order passed by learned Single Judge is having very serious financial implication across the State, even though the said order has already been complied. In case the Court is not inclined to entertain the review application, the same may be disposed of as the judgement passed by learned Single Judge approved by the Division Bench may not be cited as precedent in any other cases and objections and the important question of law so raised by the respondent State may be left open to be considered in future litigation.

7. Shri Ashutosh Mani Tripathi, learned counsel appearing for the

petitioners-respondents submitted that impugned judgment under review has been passed by Hon'ble Division Bench of this Court after hearing both the parties on merits. He further contended that Hon'ble Division Bench has considered all submissions made by the parties and has passed impugned judgment in accordance with law. He further apprises that once the judgement passed by learned Single Judge has not been complied with then the petitioners as they were retired employees have preferred a contempt application, wherein upon issuance of notice, the respondents have complied with the order and all the benefits have also been extended to them without any condition. The review petition is not maintainable. There is no mistake or error apparent on the face of record. The re-hearing the matter for changing the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of review jurisdiction and the review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction.

8. We have considered the grounds taken in review based on records.

9. Present review application has been entertained by the Division Bench consisting of Hon'ble Rajesh Bindal, Chief Justice (as his Lordship then was) and Hon'ble Piyush Agrawal, Judge on 28.11.2022 and on the said date, following order was passed:-

"1. Review of order dated December 2, 2020 has been sought by filing the present application. The issue raised is that the Circular of Government dated October 17, 1985 will not be applicable in the case of the respondents as they were substantively appointed in the Trade Tax Department on March 29, 1995 and were promoted as Nayab Tehsildar, Trade Tax on June 6, 1995. The benefit of 1985 Circular will be available to only those employees, who don't get any promotion within the period prescribed in the Circular. It was further argued that as per admitted case of the respondents they were substantively appointed even in the Revenue Department in the years 1985-86 and not in the year 1977-78 as is sought to be claimed.

2. To this, learned counsel for the respondents submitted that it has been specifically pleaded in the writ petition that prior to their regular appointment in the years 1985-86, the respondents were working with the Revenue Department as Collection Amins from the year 1977-78. He further submitted that benefit of 1985 Circular was given to the respondents after they completed 10 years of service in the years 1986-87. It is only that the second promotional grade was not given, which was due to them on completion of 14 years of service. He has referred to the supplementary affidavit filed by the State in May, 2016, admitting that the respondents were given benefit of higher pay scale on completion of 10 years of service in the years 1987-88. Once that is so, the respondents will be entitled to the next higher grade on completion of 14 years of service as well in the years 1991-92.

3. Learned counsel for the State seeks time to ascertain the fact as admitted in the supplementary affidavit filed in the year 2016 regarding grant of higher pay scale to the respondents on completion of 10 years of service in the years 1987-88.

4. Adjourned to January 16, 2023."

10. Thereafter, vide an order dated 20.2.2023 the matter has been assigned to the present Bench.

11. The review application can be allowed only on (1) discovery of new and important matter of evidence which, after exercise of due diligence, was not within the knowledge of the person seeking review, or could not be produced by him at the time when the order was made, or (2) when some mistake or error on the face of record is found, or (3) on any analogous ground. But review is not permissible on the ground that the decision was erroneous on merits as the same would be the province of an Appellate Court.

12. In the case of **Satyanarayan Laxminarayan Hegde v. Mallikarjun Bhavanappa Tirumale**, AIR 1960 SC 137, Hon'ble Supreme Court has made the following observations in connection with an error apparent on the face of the record :-

"An error which has to be established by a long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions can hardly be said to be an error apparent on the face of the record. Where an alleged error is far from self-evident and if it can be established, it has to be established, by lengthy and complicated arguments, such an error cannot be cured by a writ of certiorari according to the rule governing the powers of the superior Court to issue such a writ.

In our view the aforesaid approach of the Division Bench dealing with the review proceedings clearly shows that it has overstepped its jurisdiction under Order 47, Rule 1, C.P.C. By merely styling the reasoning adopted by the earlier Division Bench as suffering from a patent error. It would not become a patent error or error apparent in view of the settled legal position indicated by us earlier. In substance, the review Bench has re appreciated the entire evidence, sat almost as Court of appeal and has reversed the findings reached by the earlier Division Bench Even if the earlier Division Bench findings regarding C.S. Plot No. 74 were found to be erroneous, it would be no ground for reviewing the same, as that would be the function of an appellate Court. Learned counsel for the respondent was not in a position to point out how the reasoning adopted and conclusion reached by the Review Bench can be supported within the narrow and limited scope of Order 47, Rule 1, C.P.C. Right or wrong, the earlier Division Bench judgment had become final so far as the High Court was concerned. It could not have been reviewed by reconsidering the entire evidence with a view to finding out the alleged apparent error for justifying the invocation of review powers. Only on that short ground, therefore, this appeal is required to be allowed. The final

decision dated 8th July, 1986 of the Division Bench dismissing the appeal from appellate decree No.569 of 1973 insofar as C.S. Plot No. 74 is concerned as well as the review judgment dated 5th September, 1984 in connection with the very same plot, i.e. C.S. Plot No. 74 are set aside and the earlier judgment of the High Court dated 3rd August, 1978 allowing the Second Appeal regarding suit plot No. 74 is restored. The appeal is accordingly allowed. In the facts and circumstances of the case, there will be no order as to costs."

13. In the case of **Shivdeo Singh v. State of Punjab**, AIR 1963 SC 1909, Hon'ble Apex Court took the view that there is nothing under Article 226 of the Constitution of India, which precludes High Court from exercising the power of Review, which inheres in every Court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it. It was held that the power of review under Article 226 of the Constitution of India, in reviewing its own orders, every Court including High Court inheres plenary jurisdiction, to prevent miscarriage of justice or to correct grave and palpable errors committed by it.

14. In the case of **Bhagwant Singh Vs. Deputy Director of Consolidation & another**, AIR 1977 All. 163, this Court rejected the review application filed on a ground which had not been argued earlier because the counsel, at initial stage, had committed mistake in not relying on and arguing those points, held as under:-

"It is not possible to review a judgment only to give the petitioner a fresh inning. It is not for the litigant to judge of counsel's wisdom after the case has been decided. It is for the counsel to argue the case in the manner he thinks it should be argued. Once the case has been finally argued on merit and decided on merit, no application for review lies on the ground that the case should have been differently argued."

15. Hon'ble Apex Court in the case of **A.P. Sharma v. A.P. Sharma**, 1979 (4) SCC 389, has cautioned that power of review of High Court is not the same as appellate powers and review on the ground that certain documents have not been considered, which formed the record, cannot be ground of Review. Hon'ble Apex Court in the case of **Meera Bhanja v. Nirmla K. Chaudhary**, 1995 (1) SCC 170, has taken the view that review must be confined to error apparent on the face of record, error must be such as would be apparent on mere looking without any long drawn process of reasoning, and reappraisal of evidence on record for finding out error would amount to exercise of appellate jurisdiction, which is not at all permissible.

16. In **Parsion Devi and Ors. v. Sumitra Devi and Ors.** (1997) 8 SCC 715, it was held as follows:

"Under Order 47, Rule 1 CPC., a judgment may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by a process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review under Order 47, Rule 1, CPC. In exercise of the jurisdiction under Order 47, Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be "reheard and corrected". A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be "an appeal in disguise."

17. Hon'ble Apex Court, in the case of **Lily Thomas v. Union of India**, AIR 2000 SC 1650, after considering the dictionary meaning of word "review" has taken the view that power of review can be exercised for correction of mistake and not to substitute a view. Such powers can be exercised within the limits of the statute, dealing with exercise of power; the review cannot be treated as an appeal in disguise, and mere possibility of two views on the subject is not a ground of Review.

18. Hon'ble the Apex Court in **Subhash Vs. State of Maharashtra & another**, AIR 2002 SC 2537, emphasized that Court should not be misguided and should not lightly entertain the review application unless there are circumstances falling within the prescribed limits for that as the Courts and Tribunal should not proceed to re-examine the matter as if it was an original application before it for the reason that it cannot be a scope of review. In **State Haryana v. Mohinder Singh**, JT 2002 (1) 197, the Apex Court disapproved the judgment of High Court, wherein earlier writ petition was disposed of by High Court being infructuous and giving some directions, and subsequent to the same, review was sought, which was allowed, same was clearly termed to be overstepping of jurisdiction, and amounting to giving of one more chance of hearing.

19. In the case of **Union of India v. B. Valluvar**, 2006 (8) SCC 686, Hon'ble Apex Court has again considered the parameters of review jurisdiction of High Court, that same shall be exercised within the limitations as provided under Section 114 read with Order 47 Rule of C.P.C., and without recording finding as to there existed error apparent on the face of the record, merit cannot be gone into. Hon'ble Apex Court in the case of **State of Haryana and others v. M.P. Mohila**, 2007 (1) SCC 457, has taken the view that in the garb of clarification application, recourse to achieve the result of review application, cannot be permitted, as what an not be done directly, cannot be done indirectly.

20. In **The Govt. of Tamil Nadu v. Registration Department**

SC/ST and M.B.C. Employees General Welfare Sangam
MANU/ TN/ 0032/ 2006 : 2006 (1) CTC 161, it was held that review of judgment or order is contemplated to correct some mistake or error apparent on face of record; but not substitute a view. Power of review cannot be exercised to seek review of judgment already delivered for purpose of rehearing and fresh decision in case. Review cannot be an appeal in disguise. Phrase "any other sufficient cause" occurring in Order 47, Rule 1 must mean reason sufficient on grounds at least analogous to those specified in rule. Power of review may be exercised on discovery of new and important matter and evidence which after exercise of due diligence was not within knowledge of persons seeking review or could not be produced by person seeking review.

21. On the touchstone of the dictum noted above, the review is permissible only when there is error apparent on the face of record i. e. error should be grave and palpable, and the error must be such as would be apparent on mere looking of record, without requiring any long drawn process of reasoning, and reappraisal of entire evidence for finding the error, as the same would amount to exercise of appellate jurisdiction. Further, the review lies only on the grounds mentioned in Order 47, Rule 1 read with Section 141 of CPC. The party must satisfy the Court that the matter or evidence discovered by it at a subsequent stage could not be discovered or produced at the initial stage though it had acted with due diligence. A party filing a review application on the ground of any other "sufficient reason" must satisfy that the said reason is analogous to the conditions mentioned in the said provision of C.P.C.

22. From a careful perusal of judgement of learned Single Judge dated 06.11.2019, it transpires that the writ petition was preferred by 12 petitioners challenging the order dated 25.3.2014 passed by the Joint Commissioner, whereby their individual representations have been rejected by passing the separate orders. Learned Single Judge while passing the judgment and order dated 06.11.2019 has observed that "*the respondents instead of examining the claim of the petitioners in the light of Government order dated 17.10.1985, which is admittedly applicable to them, had disgraced the issue and rejected their claim simply on the ground that they cannot seek parity with the Collection Amins of the Revenue Department as they were absorbed in the Trade Tax Department*". It further reveals that learned Single Judge has been pleased to quash the order dated 25.3.2014 with respect to petitioners therein and they are held entitled to first, second and third promotional pay scale

with the Selection Grade in terms of the Government Order dated 17.10.1985 read with the Government order dated 2.12.2000 by computation of the entire period of their service from the date of their initial engagement in the Revenue Department in continuing of their absorption in the Trade Tax Department till their superannuation. Accordingly, direction was issued to the State Government towards computation of the dues and interest qua to the petitioners. It is apparent that the judgement and order of learned Single Judge as upheld by the Division Bench, being related to the individual claim of the petitioners, would confine to the writ petitioners only. Thereafter, the Deputy Commissioner (Administration) vide order dated 18.12.2020 determined the fixation of salary of the petitioners and after completion of basic pay and D.A., a sum of Rs.1,24,94,515/- was paid to the petitioners on 01.02.2021. All the petitioners-respondents have retired on attaining the age of superannuation.

23. A perusal of judgment under review shows that each and every aspect of the matter has been considered and thereafter, the Special Appeal in question has been decided. There appears no apparent mistake in the judgment under review. Neither review court can examine the merit of the judgment as an appellate court nor in the garb of review petition, re-hearing of the matter cannot be permitted by this Court.

24. Consequently, in the facts of the present case and considering the facts and circumstances as well as financial implications, it is hereby provided that the judgement of learned Single Judge affirmed by the Division Bench will hold good for the writ petitioners only and will not be considered as a judgement in rem nor a binding precedent as the issues involved is left open to be decided in an appropriate case and all the questions of law are left open to be agitated by the State Government in the appropriate case.

25. Accordingly, the present review application is disposed of.

Order Date :- 16.3.2023

A.K.Srivastava/RKP